Newspaper Clips

October 27-29, 2012

October 27

Indian Express ND 27/10/2012 P4

Research at IIT-Delhi to get a booster dose: Director

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, OCTOBER 26

IIT-DELHI Director R K Shevgaonkar on Friday said the institute is going to increase its research output and encourage inter-disciplinary courses. IIT-Delhi will soon have an innovation centre to promote entrepreneurship among students.

"The Union government has approved the setting up of an innovation centre on campus. The Ministry of Human Resource Development will provide around Rs 25 crore for the centre. The project was approved recently and the centre should be in place in about six months," Shevgaonkar said.

The new innovation centre will have courses such as aesthetic design, product design, and animation.

Setting up the centre will also entail appointment of faculty members, some of whom will be experts from industries.

According to IIT officials, statistics show that the number of PhD students has increased over the years. The data collected by the institute says the number of PhD students at IITs has increased from 138 in 2010 to 199 this year.

"We are becoming more research-oriented. We want to increase the research output of the institute, but this research should be relevant and useful to society," he said. Keeping this objective in mind, IIT-Delhi will also involve post-doctoral fellows in the system.

"Right now, we have two communities — teachers and students. Teachers do not always have the time for research. The cadre of post-doctoral fellows will strengthen research activities in the institute," he said.

IIT-Delhi plans to increase collaborations with foreign universities. It wants to introduce fellowships for Ethiopian students who wish to pursue a PhD. IIT-Delhi is also helping the Mauritius government establish a research academy.

Meta university courses next session

FOUR universities are planning to start meta-university courses in the next academic session, IIT officials said on Friday.

Speaking about the Masters in Mathematics Education course, a collaboration between DU and Jamia, Shevgaonkar said, "I don't know if it is a meta-university course, it is definitely a joint degree programme. When the idea of meta-university was initiated, three areas were identified for the courses — education, public health and climate change. For conducting these courses, resources of all four universities are needed."

He said, "We want to use a lot of technology in these courses. Classes at one university will be telecast at the other three universities."

Hindustan Times ND 27/10/2012
P-9

IIT-D all set to open design innovation centre

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: A spate of new projects will soon grace the campus of the Indian Institute of Technology (IIT Delhi). While the institute has already set up its Student Innovation Centre with seed funding provided by the batch of 1986, it is now ready to set up yet another centre.

"The Government of India has approved an innovation centre to be set up at the IIT campus. This is going to be a design centre and will be different from the existing student innovation centre that already exists," said RK Shevgaonkar, director, IIT (Delhi).

Research in this innovation centre will focus more on inter-disciplinarity. Although the existing faculty will be employed for the purpose, the institute is also planning to hire trained professionals and additional faculty.

While the centre will become functional in six months' time,

THE INSTITUTE HAS RECEIVED AN INITIAL CAPITAL OF ₹25 CRORE FROM THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MHRD)

students will have several options to choose from such as aesthetic design, product design and animation.

"At present, there is a student innovation centre that operates in IIT Delhi. But the new innovation centre will float additional courses for students, such as those relating to becoming an entrepreneur. These interdisciplinary courses will make students more aware of the innovations," said Shiben Kishen Koul, deputy director (strategy and planning).

The institute has also received an initial seed capital of ₹25 crore from the Ministry of Human Resource Development (MHRD) for this purpose.

It will also teach students how to formulate an innovative idea and put it into practice.

"This centre will teach students three basics — first, how to generate an innovative idea; second, how to convert that innovative idea into a product and third, to convert that product into a business. The students will always have the option of sitting for the institute's placement process," Shevgaonkar said.

Dainik Jagaran ND 27/10/2012 P7

आइआइटी दिल्ली में खुला इनोवेशन सेंटर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली में छात्रों के लिए एक इनोवेशन सेंटर खोला गया है, जिसमें छात्र अपने मस्तिष्क में आने वाले विचारों पर प्रयोग कर नए-नए अविष्कार कर सकेंगे। खास बात यह है कि छात्रों के लिए यह केंद्र चौबीस घंटे खुलेगा। जिसे आइआइटी दिल्ली के एलुमनी छात्रों द्वारा दिए गए फंड से स्थापित किया गया है। यह सेंटर जामिया द्वारा डीयू, जेएनयू और आइआइटी दिल्ली के सहयोग से शुरू होने वाली मेटा यूनिवर्सिटी में भी उपयोगी साबित होगा।

आइआइटी दिल्ली के निदेशक आर के शिवगांवकर ने बताया कि इनोवेशन सेंटर में छात्र अपनी रचनात्कमता को नया आयाम दे सकेंगे। इस केंद्र में कुछ बुनियादी टूल, इक्विपमेंट और डिजाइन सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। अगर किसी छात्र के मन में कोई आइडिया आता है तो वह सॉफ्टवेयर की मदद से आइडिया को विजुलाइज करेगा और फिर मशीनों से उसे अंतिम रूप दे सकेगा। जैसे अगर कोई छात्र फोल्डिंग टेबल बनाना चाहता है, जिसे हॉस्टल में बेड

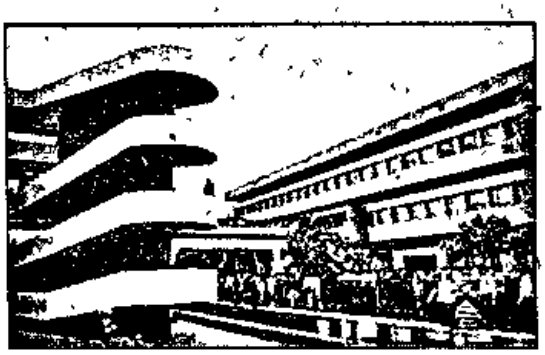

- छात्रों के लिए चौबीस घंटे तक खुला रहेगा सेंटर
- आइआइटी दिल्ली के एलुमनी छात्रों के दिए फंड से स्थापित

के नीचे रखा जा सके और पढ़ाई के समय मेज की तरह उपयोग कर सके। तो इसे बनाने में यह केंद्र मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि इसे खोलने के लिए 1976 के एलुमनी छात्रों ने फंड दिया है।

शिवगांवकर ने बताया कि छात्रों में तकनीकी कौशल बढ़ाने के साथ नए उत्पादों का सृजन और उसे बाजार में कैसे उतारा जाए? इस दिशा में भी यह केंद्र छात्रों के लिए कारगर साबित होगा।

Dainik Bhaskar ND 27/10/2012 P4

छात्रों को उद्यमी बनाएगा आईआईटी का इनोवेशन सेंटर

खुशखबरी छात्र-शिक्षकों के लिए उपलब्ध केंद्र को दिया गया विस्तार, अन्य इंजीनियरिंग संस्थान के छात्र-छात्राएं भी कर पाएंगे काम

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, दिल्ली में छात्रों-शिक्षकों के लिए काम कर रहे इनोवेशन सेंटर को विस्तार दिया जा रहा है। कैम्पस में उपलब्ध यह सेंटर अब अन्य संस्थानों के इंजीनियरिंग के छात्रों को उनकी नई सोच के साथ एक काबिल टेक्नोक्रेट बनाने में मददगार साबित होगा। आईआईटी, दिल्ली की ओर से अंजाम दी गई इस कोशिश का मूल उद्देश्य कहीं न कहीं छात्रों को बेहतर उद्यमी के तौर पर विकसित करना है। चौबीस घंटे सातों दिन चलने वाले इस केंद्र को आईआईटी एलुमनी के फंड से किया गया था जिसे विस्तार प्रदान करने के लिए मंत्रालय से 25 करोड़ रुपए मिले हैं। जल्द ही इस केंद्र में आईआईटी दिल्ली के साथ आईआईटी दिल्ली, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईटी, मंडी के छात्र-छात्राएं अपनी रिसर्च से जुड़े कार्य कर पाएंगे।

आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो.आर.के.शिवगांवकर के मुताबिक इनोवेशन सेंटर में छात्र अपनी रचनात्मकता को नए आयाम दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में कुछ बुनियादी टूल, उपकरण और डिजाइनिंग से जुड़े सॉफ्टवेयर उपलब्ध रहेंगे। इनकी मदद से छात्र के मन में यदि कोई सुझाव या नया आइडिया विकसित होता है तो वह पहले उसे उपलब्ध सॉफ्टवेयर की मदद से विजुलाइज कर सकेंगे और फिर मशीन के द्वारा उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। जैसे कोई छात्र फोल्डिंग टेबल बनाना चाहता है जो कि हॉस्टल के कमरे में बेड के नीचे रखी जा सके और पढ़ाई के दौरान उसे मेज के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सके। इस तरह के आइडियाज को लेकर जब छात्र इनोवेशन केंद्र में आएगा तो वह मशीन की मदद से अपने विचारों को मूर्त रूप देने की दिशा में बढ़ेगा और इसके लिए सेंटर उसे गाइडेंस उपलब्ध कराएगा। इस केंद्र की शुरुआत के लिए आईआईटी दिल्ली के 1986 बैच के छात्रों ने आर्थिक मदद मुहैया कराई है, जिसे अब विस्तार दिया जा रहा है और इसके लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की ओर से 25 करोड़ रुपए मिले हैं। विस्तार कार्य को अगले छह माह में पूरा कर लिया जाएगा। प्रो. शिवगांवकर कहते है कि आईआईटी के छात्र तकनीकी के मामले में सामान्य छात्रों से आगे होते हैं। इस सेंटर का मकसद है कि टेक्नोलॉजी बनाने के साथ-साथ उसे एक उत्पाद के तौर पर बाजार में कैसे उतारा जाए इसके लिए भी पहले से ही तैयारी कर ली जाए।

आईआईटी दिल्ली मेटा सिस्टम की ओर

नई दिल्ली. मेटा यूनिवर्सिटी सिस्टम के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद अब आईआईटी दिल्ली ने भी रिसर्च के क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इनके लिए वह डीयू, जामिया, जेएनयू किसके साथ काम करेगी। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. आर.के.शिवगांवकर ने कहा कि हम मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा के तहत शिक्षा, पब्लिक हेल्थ और मौसम परिवर्तन से जुड़े कोर्स शुरू करना चाहते हैं लेकिन इससे पहले इन क्षेत्रों में रिसर्च कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिलकर काम करने को लेकर सभी संस्थानों के साथ बैठक में चर्चा की गई थी कि चारों संस्थानों का एक कार्यालय बनाये जाने से लेकर, छात्रों का चयन कैसे होगा और कौन क्या भूमिका निभाएगा इस दिशा में विचार हुआ है। हालांकि आईआईटी, दिल्ली का कहना है कि इस दिशा में किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से अभी कोई समझौता नहीं हुआ है।

Hari Bhumi ND 27/10/2012 p-2

प्रयास | एलुमनी के फंड से आईआईटी दिल्ली में खुला इनोवेशन सेंटर

विचारों को देख सकेंगे आईआईटी के छात्र

हरिभूमि न्यूज. नई दिल्ली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में पढ़ने वाले छात्र के दिमाग में जैसे ही कोई आइडिया आएगा वह उसें सॉफ्टवेयर के माध्यम से विजुअलाइज कर यह देख सकेगा कि उसका आइडिया कैसा है। छात्रों के इनोवेशन को मूर्त रूप देने के लिए ही संस्थान में एक सेंटर खोला गया है।

सफलता के खुले द्वार

यह सेंटर छात्रों को एक काबिल टेक्नोक्रेट के साथ-साथ बेहतर उद्यमी बनाने में मददगार साबित होगा। चौबीस घंटे काम करने वाला यह केंद्र

आईआईटी के एलमुनी द्वारा दिए गए फंड से शुरू किया गया है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक आर.के. शिवगांवकर ने बताया कि इनोवेशन सेंटर में छात्र अपनी रचनात्कमता को नया आयाम दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में कुछ बुनियादी टूल, इक्विपमेंट और डिजाइन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। ऐसे में जैसे ही छात्र के मन में कोई आइडिया आएगा वह उसे सबसे पहले सॉफ्टवेयर से विजुअलाइज करेगा। इसके बाद मशीन के द्वारा उसे अंतिम रूप दे सकेगा। छात्र के आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र उसे मशीन उपलब्ध कराने के साथ ही उसे गाइड भी करेगा। गौरतलब है कि इस केंद्र को खोलने के लिए आईआईटी दिल्ली के 1976 बैच के छात्रों ने फंड दिया है।

मेटा पर विचार-विमर्श जारी

आईआईटी दिल्ली में जल्द ही मेटा विश्वविद्यालय के तहत चार कोर्सों को शुरू किया जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया और जवाहरलाल नेहरू विवि के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक आर.के.शिवगांवकर ने कहा कि मेटा विवि की अवधारणा के तहत शिक्षा, पब्लिक हेल्थ और मौसम परिवर्तन से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस पर कब तक कोर्स शुरू किया जाएगा, विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में चर्चा की गई थी कि चारों संस्थानों का एक कार्यालय बनाया जाए, छात्रों का चयन कैसे होगा, यह तय किया जाए। वैसे संभावना यह जताई जा रही है कि आईआईटी पहले रिसर्च संबंधी समझौता ही इन विश्वविद्यालयों के साथ करेगा।

Hindustan ND 27/10/2012 P5

आईआईटी में 24 घंटे आइडिया का स्वागत है

नई दिल्ली | अनुराग मिश्र

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी) में छात्रों के लिए एक इनोवेशन सेंटर खोला गया है। यह सेंटर छात्रों को एक काबिल टेक्नोक्रेट के साथ-साथ बेहतर उद्यमी बनाने में मददगार साबित होगा। चौबीस घंटे और पूरे हफ्ते काम करने वाला ये केंद्र आईआईटी के एलमुनी द्वारा दिए गए फंड से शुरू किया गया है।

आईआईटी दिल्ली के निदेशक आर.के.शिवगांवकर ने बताया कि इनोवेशन सेंटर में छात्र अपनी रचनात्कमता को नया आयाम दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में कुछ बुनियादी टूल, इक्विपमेंट और डिजाइन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। ऐसे में छात्र के मन में यदि कोई आईडिया आता है तो वह पहले उसे सॉफ्टवेयर से उसे विजुलाइज कर सकेगा और फिर मशीन के द्वारा उसे अंतिम रूप दे सकेगा।

उदाहरण के तौर पर यदि कोई छात्र फोल्डिंग टेबल बनाना चाहता है जिसको हॉस्टल के कमरे में बेड के नीचे रखा जा सके और पढ़ाई के दौरान उसे मेज के तौर पर प्रयोग किया जा सके। ऐसे में केंद्र इसे बनाने के लिए मशीन उपलब्ध कराएगा और छात्रों को वर्कशॉप के द्वारा उनके विचारों को मूर्त रूप देने के लिए गाइड भी करेगा। इस केंद्र को खोलने के लिए आईआईटी दिल्ली के 1986 के छात्रों ने फंड दिया है। शिवगांवकर ने बताया कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मंडी और आईजीआईटी के छात्र-छात्राएं यहां काम कर सकेंगे।

नया आयाम

पॉलिसी स्टडीज की पढ़ाई होगी

आईआईटी दिल्ली में पॉलिसी स्टडीज की पढ़ाई शुरू होगी। इसे लघु विषय के तौर पर शुरू किया जाएगा। उपनिदेशक (रणनीति और योजना) शिव किशन कौल ने बताया कि इस तरह के विषय की पढ़ाई फिलहाल देश के किसी संस्थान में नहीं होती है। इसमे तकनीक से जुड़े क्षेत्रों आईटी, मैकेनिकल, केमिकल की नीतियों और तौर-तरीकों के बारे में पढ़ाया जाएगा।

मेटा के तहत चार कोर्स चलेंगे

आईआईटी दिल्ली ने कहा कि मेटा विश्वविद्यालय के तहत चार कोर्सों को शुरू किया जाएगा लेकिन इस बाबत अभी डीयू, जामिया, जेएनयू से किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक आर.के.शिवगांवकर ने कहा कि मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा के तहत शिक्षा, पब्लिक हेल्थ और मौसम परिवर्तन से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे। डीयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जेएनयू से इस बारे में अंतिम रूप से समझौता नहीं हुआ है।

इनोवेशन सेंटर छात्रों के आइडिया को साकार करेगा। इसमें छात्र टेक्नोलॉजी के साथ-साथ उत्पाद को बाजार में उतारने की कला भी सीखेंगे।

आर.के.शिवगांवकर, निदेशक, आईआईटी दिल्ली

आईआईटी और एम्स साथ-साथ

आने वाले समय में आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान कुछ विषयों की पढ़ाई साथ करा सकते हैं। आईआईटी दिल्ली के निदेशक ने कहा कि संस्थान का झज्जर में खुलने वाला केंद्र एम्स के काफी नजदीक है। ऐसे में इस बात पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि शोध कार्य और पढ़ाई के क्षेत्र में दोनों संस्थान मिल कर काम करें।

Times of India ND 27/10/2012 P9

IIT-D: Meta-course at least a year away

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Indian Institute of Technology, Delhi (IIT-D) will take another year to be a part of the meta-university concept. Unlike Delhi University and Jamia Millia Islamia which recently announced the country's first meta-university course, masters' in mathematics education, IIT-D doesn't have any imminent plans of starting any academic programme as part of the project. The institute, which is in talks with JNU for collaborative research activities under the project, is set to have a design innovation centre.

Speaking about the meta-university concept, IIT-D director, R K Shevgaonkar, said, "We had talks with JNU, but the plan will take another year or so to materialize. We also held discussions with DU and Jamia, but are yet to finalize the modalities. We want to start research collaboration with JNU in areas of public health, climate change and education." When IIT-D decides to launch academic programmes, students will get joint degrees with logos of all the four participating institutes.

The design innovation centre will help students with entrepreneurial minds transform their ideas into products. It is expected to be functional in another six months. The centre has got the nod of the HRD ministry which has extended financial aid of Rs 25 crore for its construction.

Meanwhile, IIT-D's 43rd convocation, on Sunday, will see the largest number of postgraduates and PhD holders (1006 and 199 respectively). In a first, graduates, postgraduates and PhDs will be conferred degrees on the same day.

IIT-D is also introducing awards for distinguished alumni — amounting to Rs 5 crore — this year onwards. The alumni that will receive the awards are professor Trilochan Sastry of IIM, Bangalore, professor R C Budhani, director, National Physical Laboratory, New Delhi, Punita Kumar Sinha, founder and managing partner, Pacific Paradigm Advisors and professor Pawan Sinha, Massachussetts Institute of Technology, USA.

Navbharat Times ND 27-Oct-12 P-4

मेटा : आईआईटी का फोकस रिसर्च पर

भूपेंद्र ॥ नई दिल्ली

मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट में अब आईआईटी दिल्ली की भी भागीदारी होने जा रही है। फर्स्ट फेज में रिसर्च प्रोग्राम के लिए टाईअप होगा। मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को लागू करते हुए जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने मिलकर मास्टर ऑफ मैथमैटिक्स एजुकेशन कोर्स लॉन्च कर दिया, वहीं आईआईटी दिल्ली अकैडमिक प्रोग्राम शुरू करने से पहले रिसर्च को लेकर आगे बढ़ना चाहती है।

आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर आर. के. शिवगांवकर ने बताया कि मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट में आईआईटी दिल्ली, डीयू, जेएनयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मिलकर कोर्स चलाने हैं और स्टूडेंट्स को दी जाने वाली डिग्री पर चारों संस्थानों के नाम होंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेकर शुरुआत में जो योजना बनी थी, उसे फॉलो किया जा रहा है। अभी जेएनयू से रिसर्च प्रोग्राम को लेकर बात चल रही है और डीयू से भी बातचीत होगी। जिन तीन एरिया में रिसर्च प्रोग्राम होंगे, उनमें एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और क्लाइमेट चेंज जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं।

डायरेक्टर के मुताबिक एक साल के बाद अकैडमिक प्रोग्राम शुरू होंगे। इसमें ऐसे कोर्स शुरू होंगे, जिनमें अलग-अलग सब्जेक्ट चारों संस्थानों में पढ़ाए जा सकें। उन्होंने बताया कि मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट में आईआईटी दिल्ली और बाकी तीनों यूनिवर्सिटीज को बराबरी का मौका मिलना है। ऐसा कोई कोर्स शुरू नहीं किया जा सकता, जिसके कंटेंट केवल एक यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाए जा सकते हों। आईआईटी दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर (ऑपरेशंस) प्रो. एस. एन. सिंह ने बताया कि कैंपस में आने वाले छह महीने में इनोवेशन डिजाइन सेंटर बनाया जाएगा। एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसके लिए अप्रूवल दे दी है और शुरुआत में 25 करोड़ रुपये की लागत से यह सेंटर बनाया जाएगा। आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए यह सेंटर काफी फायदेमंद साबित होगा। स्टूडेंट्स नए-नए डिजाइन बना सकेंगे और उन्हें खास ट्रेनिंग मिलेगी। इस सेंटर में डिजाइन पर आधारित कोर्सेज शुरू होंगे और इन कोर्सेज का क्रेडिट भी उन्हें मिलेगा। कोर्स स्ट्रक्चर में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। एक महीने पहले ही एचआरडी मिनिस्ट्री से सेंटर बनाने की अप्रूवल मिली है। यहां पर इनोवेशन सेंटर पहले से ही है। आईआईटी दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर (स्ट्रैटजी एंड प्लानिंग) प्रो. शिबन किशन कौल के मुताबिक ग्रैजुएशन, पोस्ट ग्रैजुएशन और रिसर्च कर रहे सभी स्टूडेंट्स को इनोवेशन डिजाइन सेंटर से जुड़ने का मौका मिलेगा।

कॉन्वकेशन में 1786 डिग्रियां दी जाएंगी

प्रस ॥ नई दिल्ली : आईआईटी दिल्ली 43वां दीक्षांत समारोह 28 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस बार डिग्री पाने वाले स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा हैं। आईआईटी के मुताबिक 1786 डिग्रियां दी जाएंगी, जबकि 2011 में 1495 डिग्रियां दी गई थीं।

पीएचडी की 199, पीजी लेवल पर 1006 और ग्रैजुएशन कोर्सेज की 586 डिग्रियां स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। डिग्री पाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या 294 है। आईआईटी दिल्ली में इस समय 7777 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आईआईटी के डायरेक्टर आर. के. शिवगांवकर के मुताबिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पीएचडी की डिग्री हासिल करें। इस बार एलुमनी अवॉर्ड भी शुरू किए गए हैं। दीक्षांत समारोह में ये अवॉर्ड भी दिए जाएंगे।

Amar Ujala ND 27/10/2012

P-8

आईआईटी दिल्ली का अगला पड़ाव झज्जर

● अमर उजाला ब्यूरो

● भाड़सा गांव में जमीन के लिए हो रही है बात

● एम्स कैंपस के नजदीक होगा सेंटर

नई दिल्ली। हरियाणा के सोनीपत स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में कैंपस बनाने के बाद आईआईटी दिल्ली अब अगला सेंटर हरियाणा के ही झज्जर में स्थापित करेगी। रिसर्च कैंपस के लिए झज्जर के गांव भाड़सा में 125 एकड़ अतिरिक्त जमीन दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार से बात चल रही है। आईआईटी को उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में निर्णय ले लिया जाएगा।

आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर आर के शेवगांवकर ने बताया कि संस्थान में तमाम गतिविधियां होती हैं, जिनके विस्तार की जरूरत है। कुछ ही समय पहले अपना सेंटर बनाने के लिए सोनीपत स्थित कुंडली के राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में 50 एकड़ जमीन की मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि अब झज्जर के पास 125 एकड़ जमीन की मांग की गई है। इस बारे में हरियाणा सरकार से बातचीत जारी है। एम्स कैंपस भी इसी जगह के पास बन रहा है, लिहाजा भविष्य में दोनों संस्थानों को लाभ मिलेगा।

प्रोफेसर शेवगांवकर ने बताया कि यह एक रिसर्च कैंपस होगा, लिहाजा विभिन्न कोर्स से संबंधित गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। आईआईटी का मानना है कि रिसर्च कैंपस के बनने से भारत भी रिसर्च के क्षेत्र में काफी आगे जाएगा।

मेटा यूनिवर्सिटी के लिए भी तैयार

अब आईआईटी भी मेटा मॉड अपनाने के लिए तैयार है। इसके लिए आईआईटी ने शिक्षा, पब्लिक हेल्थ और क्लाइमेंट चेंज का चुनाव किया है। प्रो शेवगांवकर के मुताबिक, ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं, जिस पर कोई भी संस्थान काम नहीं कर रहा है। चारों संस्थानों से रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए तीन-तीन सदस्य होंगे, जो कि इन चुने गए क्षेत्रों की रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि अभी शोध कार्यों के लिए समझौता हुआ है, बाद में कोर्स शुरू करने के बारे में सोचा जाएगा।

संस्थान का 43वां दीक्षांत समारोह कल

आईआईटी दिल्ली रविवार को अपना 43वां दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है। समारोह में देश के भावी इंजीनियरों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री के नेशनल काउंसिल ऑफ स्किल डेवलपमेंट सलाहकार एस रामादोराई समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस बार कुल 1786 डिग्री प्रदान की जा रही हैं, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 1495 था। इस बार 199 छात्रों को पीएचडी की डिग्री दी जाएगी, जबकि बीते साल 173 छात्रों को ही यह डिग्री हासिल हुई थी।

इनोवेशन सेंटर को मिलेगा विस्तार

नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के 1986 बैच के छात्रों के फंड से फरवरी में शुरू हुए स्टूडेंट इनोवेशन सेंटर को जल्द ही विस्तार मिलने वाला है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेंटर को आगे बढ़ाने के मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि करीब छह माह में यह शुरू हो जाएगा। सेंटर को शुरू करने के पीछे आईआईटी का उद्देश्य छात्रों को उद्यमी के तौर पर तैयार करना है। खास बात यह है कि इसमें बाहर के छात्रों को भी मौका मिलेगा। इस पर कुल 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी। आईआईटी निदेशक प्रो आर के शिवगांवकर ने बताया कि यह एक तरह से डिजाइन इनोवेशन सेंटर होगा। इसमें छात्रों को प्रोडक्ट को डिजाइन करने के साथ ही उसे बाजार में बेचने की कला से रूबरू कराया जाएगा। इसमें ट्रिपलआईटी दिल्ली, आईआईटी मंडी और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी दिल्ली के छात्र रिसर्च कर सकेंगे। *ब्यूरो*

Statesman ND 27/10/2012 p-2

IIT-Delhi convocation tomorrow

NEW DELHI, 26 OCT: Indian Institute of Technology, Delhi (IIT-D), will hold its 43rd convocation on Sunday in which 1,786 students will get degrees. The Prime Minister's advisor on the national council development, Mr S Ramadorai, will be the chief guest.

Degrees will be awarded to 199 Phd, 1,006 post graduate and 586 undergraduate students. IIT Delhi will also honour four alumni — Prof Trilochan Sastry (BTech Electrical Engg in 1981), Dr Punita Kumar Sinha (B.Tech in Chemical, 1985), R C Budhani (Phd Physics 1982) and Prof Pawan Sinha (B.Tech 1988).

"We are going to help the Mauritius government set up an establishment like IIT Delhi and expand their campus in Haryana too," said the director of IIT, Delhi, Prof R K Shevgaonkar.

He criticised both Delhi University and Jamia Millia Islamia for not including IIT-Delhi in mathematics course based on meta university concept. He said, "The meta university project was meant to be started jointly by all the universities in Delhi, like Delhi University, Jamia Millia Islamia, Jawaharlal Nehru University and IIT-Delhi. We all planned to work on this meta university concept collectively and even decided topics for the research. However, DU and Jamia both have jointly started a course." **sns**

Innovation centre for under-graduates

NEW DELHI, 26 OCT: Indian Institute of Technology Delhi (IIT-D) is going to set up an innovation centre for undergraduate students at its campus to help them develop entrepreneurship skills. The director of IIT-D, Prof R K Shevgaonkar, said, "After graduating from IIT, students are well prepared for their jobs but most of them lack entrepreneurship skills. Therefore, to develop this, IIT-D took the initiative." The innovation centre will teach students about various innovations. Among the key courses will be animation, study of designing, etc. Prof Shevgaonkar said, "Apart from the students of IIT-D, other students of IIT-Mandi and Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi, can also participate. All the students, who will be part of the project will not only learn about developing new things but also learn how to sell the newly made things." The centre will be based on research-orientated programmes and is likely to come up in the next six months. "We had a discussion with the ministry of human resource development and they have given the nod to set up the centre for the students," he said. sns

HT Mumbai

Coaching classes woo city's JEE students with discounts, waivers

OPPORTUNITY Promising students will get scholarships, a chance to visit NASA, CERN and Singapore

Bhavya Dore
bhavya.dore@hindustantimes.com

MUMBAI: Students preparing for the Joint Entrance Exam (JEE) don't have just a place in the Indian Institutes of Technology to look forward to as a reward. If they do well, they might even get paid for their efforts. In cash, and lots of it.

Coaching classes are offering bigger fee waivers, discounted rates and scholarships for promising students, as well as larger prize money for toppers. This year, IIT-ians PACE will offer cash prizes for the first time, with Rs20 lakh for the topper at JEE 2013. The quantum of money set aside for scholarships has also been amped up from Rs2 crore to Rs5 crore.

Coaching class Resonance has increased its overall cash prize value by 50%, to Rs75 lakh from Rs50 lakh. At Aakrati, students who do well will have their engineering college fees paid every year. "We are doing it voluntarily by using the money from our profit to ensure that deserving students don't lose out," said Praveen Tyagi director, PACE.

Apart from offering larger prize money to good performers, many institutes also run scholarship programmes for school students and for poor students who are unable to bear the prohibitive costs of coaching.

Both FIITJEE and Resonance recently conducted tests to identify candidates for their annual scholarship programmes. Resonance's START programme is for any student across the country, and toppers from each class will be rewarded with cash prizes and will also stand a chance to win a trip to NASA, CERN or Singapore. Students can also win other merchandise.

"The idea is to identify talent from across the country," said Manoj Sharma, vice president, operations and business development, Resonance. "It is also a branding activity for us."

Institutes say that such prizes act as a good incentive. "It motivates everyone to work towards something," said RK Sharma, director, Aakrati.

PRIZES AWARDED BY VARIOUS COACHING CLASSES

SHRIKRISHNA

The scholarship amount for students has been increased by IIT-ian's Pace from **₹2 crore to ₹5 crore**. The JEE topper will get **₹20 lakh**, second ranker **₹10 lakh**, and there will be seven **₹5 lakh** prizes.

Resonance Scholarship and Talent Reward Test 2013, open to school students from Class 5 to Class 12, has a top prize of a NASA trip for every class topper, a CERN trip for every second ranker and a Singapore trip for every third ranker. Subsequent rankers will get computers, watches and other merchandise.

Aakrati will pay engineering college fees for deserving students after they finish Class 12.

FIITJEE scholarship programme rewards students from Class 5 to Class 11 with cash prizes and fee waivers. JEE toppers will get cash and a plaque.

For details about the new JEE (Advanced) candidates can check http://www.jee.iitb.ac.in/ and www.cbse.nic.in for more information on JEE (Main).

Times of India ND 27/10/2012 P6

Hundreds gather in DU for joint protest against VC

TIMES NEWS NETWORK

Sanjay Sekhri

NO END TO IMPASSE: Another protest is planned on October 31

New Delhi: The joint forces of the three main associations of DU — Delhi University Teachers' Association, Delhi University and College Karamchari Union, and the Delhi University Students' Union — are shaping into a power to reckon with. Hundreds gathered for the protest on the premises of the vice-chancellors' office in North Campus on Friday. Another protest is planned for October 31.

The teachers had already started an indefinite relay-hunger-strike on October 10. The coming-together of the three associations drew a large number of students and even one odd parent.

Mamta Saxena had come from Sonepat to protest against the university's decision to withdraw the "special chance rule" allowing students to write papers they had missed or failed to clear, later. Her daughter has Hodgkin's Lymphoma (cancer of the lymph tissue) and was unable to clear one paper in her second-year exam. "She is an Economics (H) student and wrote her final exams even while undergoing chemotherapy. But now the university is not allowing her to write her second-year paper," adds Saxena.

Ann Mary, a final-year law student joined the protest for similar reasons. Health problems kept her from writing her final-year exams and now she is barred from reappearing. "You have to apply rules prospectively, not retrospectively. We took the decisions then believing the special chance rule was still in force," she says. A petition was circulated, and students and teachers lined up to sign. According to members of the joint "coordination committee", they would decide on the course of action later. The protest was also a site for a fundraiser and over Rs 7,300 were raised for fliers.

Teacher-activists from Jamia Millia Islamia, AMUTA and JNU shared the dais alongside the DUTA, DUSU and DUCKU office-bearers.

Mail Today ND 27/10/2012 P-12

Bihar's 'super' highway to IIMs

By **Giridhar Jha**
in Patna

CIMP, set up by Bihar CM Nitish Kumar in 2008, has launched Students' Guidance Centre.

INSPIRED by the coaching centre Super 30, a management institute in Bihar is helping underprivileged students to make it to the Indian Institutes of Management (IIMs) and other prestigious business schools.

The Chandragupt Institute of Management Patna (CIMP), an autonomous management institute set up by the Nitish Kumar government in 2008, has launched a unique institution called Students' Guidance Centre (SGC) to provide free coaching to bright students from the SC, ST and OBC categories to crack various management entrance tests.

Trains poor students for CAT, XAT & IRMA

Its efforts have already produced remarkable results with several students clearing CAT with high percentile and getting calls from IIMs at various centres including Kozhikode, Kolkata, Lucknow and Ranchi.

Institute's three students.— Sandeep Choudhary, Ravindra Kumar and Hemant Kumar — cracked CAT this year.

Last year, three SGC-trained students got through CAT's written examination and 25 got jobs as bank officers and one even received an invitation from NASA.

In 2010, 40 of its students had appeared for CAT. Of them, six got calls from IIMs, IRMA and other management institutions while two more, Tarique-ur-Rahman and Varun Kumar, got selected in IIM-Lucknow and IIM-Raipur respectively.

Tarique said the centre not only trained him for CAT but also made him aware about other career options. "It is a non-profitable institute that works with the sole motive of success of its students," he said.

Ravindra, a farmer's son who made through six IIMs, said: "I had never thought I would get selected in an IIM. Things changed dramatically, after I enrolled at SGC. Their training gave me the ability and confidence to appear for CAT."

The difference between success and failure is often determined by the availability of opportunities. At SGC, opportunities are aplenty," Sandeep, who received interview calls from seven IIMs, said.

A brainchild of CIMP director Prof V. Mukunda Das, SGC focusses on the accelerated development of Bihar by providing educational access to the poor but bright students of the state, aspiring for admission into reputed management institutes such as IIMs. Apart from CAT, the students also get training for other competitive examinations.

"Bihar has Super 30 for poor students, we have set up SGC, that trains deprived students for top management institutes," Das, who was a part of IIM-Kozhikode faculty, said.

"While Anand Kumar's Super 30 is a batch of 30 students, SGC selects 75 students annually — 50 from SC/ST category and 25 from OBCs," Das added.

SGC aspired to be a catalyst in bringing about a radical change in Bihar's educational profile by developing the competency among the socially and economically backward students, he added.

The students are selected on the basis of a written test and an interview. Once selected, they are provided free coaching, counselling and personality development for six months.

The students also get a scholarship of ₹1,000 per month, besides learning aids. SGC also plans to cover students from other states and become a national centre.

THE TOOL FOR DEVELOPMENT

- **Inspired by Super 30, Students' Guidance Centre (SGC) focusses on Bihar's accelerated development**
- Provides free coaching to bright students from SC, ST and OBC to crack CAT and other entrance tests
- **Many of its students crack CAT, get calls from IIMs and other institutes every year**
- SGC selects 75 students every year — 50 from SC/ST category and 25 from OBCs
- **It coaches and counsels its students for six months**
- Provides students with all the learning aids and a scholarship of ₹1,000 per month

Financial Chronicle ND 27/10/2012 p-7

Future of genetically modified crops

Government needs to urgently develop institutional structures to allay public apprehension

M S SWAMINATHAN

I was a contemporary of James Watson and Francis Crick at the University of Cambridge, UK, during 1950-52. I was aware of the fact that they were working on the molecular structure of DNA in association with Maurice Wilkins and Rosalind Franklin since I used to visit the Cavendish Laboratory to attend lectures by Prof Max Perutz. Their publication on the double helix structure of the DNA molecule appeared in Nature early in 1953 (Watson J D and Crick FHC, 1953. "A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid" Nature, 171, 737-738) I was then at the Genetics Laboratory of the University of Wisconsin, Madison, USA. Since then, I have been following the explosive progress of the science of molecular genetics, opening up uncommon opportunities for transferring genes across sexual barriers.

In 1980, when I joined the Union Planning Commission at the invitation of the then prime minister Indira Gandhi, I set up a National Biotechnology Board to achieve synergy and coordination among the work in progress in molecular genetics and genetic engineering under the umbrella of different scientific organisations like ICAR, CSIR, ICMR, Department of Atomic Energy and UGC. I served as the first chair of the Board. Later, it was converted into the department of biotechnology during the tenure of prime minster Rajiv Gandhi, with S Ramachandran serving as its first Secretary.

During the last 30 years, the government of India has invested a considerable amount of money in creating the infrastructure essential for advanced research in the broad areas of biotechnology in general, and in genomics and genetic engineering in particular. The government is also hosting the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) in New Delhi. Both in India and abroad, much investment has been made for human resource development in the areas of environmental, medical, industrial, food and agricultural biotechnology. The first patent for a living genetically modified organism was granted to Anand Chakraborty in the US for his work on the development of a pseudomonas strain which can clean up oil spills. Genetic medicine including vaccine development is also making rapid progress. Bioremediation is gaining in importance with growing pollution of water. However, in the field of agricultural and food biotechnology, there are concerns about biosafety, environmental safety, biodiversity loss and food safety. The Global Biodiversity Convention adopted at Rio de Janeiro in June 1992 has the following clause with respect to biosafety:

"The Parties shall consider the need for and modalities of a protocol setting out appropriate procedures, including, in particular, advance informed agreement, in the field of the safe transfer, handling and use of any living modified organism resulting from biotechnology that may have adverse effect on the conservation and sustainable use of biological diversity."

This resulted in the adoption of the Cartagena Protocol for biosafety. The Cartagena Protocol is the only international environmental agreement that is concerned exclusively with the transboundary movement (that is, trade) of products of modern biotechnology that are living modified organisms. It applies to the transboundary movement, transit, handling and use of all living modified organisms that may have adverse effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking into account risks to human health. GM foods are considered only if they are LMOs that may be subject to transboundary movement for direct use as food, feed or for processing. The protocol does not apply to processed food products, nor does it address the food safety of LMOs that are for food, feed or processing. This Protocol was discussed in detail recently at Hyderabad on the Occasion of the Conference of Parties (CoP 11) of CBD.

In 2004, a committee set up by the ministry of agriculture of the government of India under my chairmanship (Report of the Task Force on Applications of Agricultural Biotechnology, May 2004, ministry of agriculture, government of India) made several recommendations of which the following is important:

"The bottom line of our national agricultural biotechnology policy should be the economic well being of farm families, food security of the nation, health security of the consumer, biosecurity of agriculture, protection of the environment, and the security of national and international trade in farm commodities".

Recently, the committee on agriculture of parliament, headed by Basudeb Acharia with 31 members of parliament drawn from both the houses (Lok Sabha and Rajya Sabha) and from all political parties has submitted a very detailed report on "Cultivation of genetically modified food crops: Prospects and Effects" (Lok Sabha Secretariat, August 2012, 492 pp).

The committee has unanimously recommended that "till all the concerns voiced in the report are fully addressed and decisive action is taken by the government with utmost priority to put in place all regulatory, monitoring, oversight, surveillance and other structures, further research and development on transgenics in agricultural crops should only be done in strict containment, and field trials under any garb should be discontinued forthwith". The committee also suggested, "What the country needs is not a biotechnology regulatory legislation but an all encompassing umbrella legislation on biosafety, which is focused on ensuring the biosafety, biodiversity, human and livestock health, environmental protection, and which specifically describes the extent to which biotechnology, including modern biotechnology, fits in the scheme of things without compromising with the safety of any one of the elements mentioned above. The committee, therefore, recommend to the government with all the power at their command to immediately evolve such a legislation after due consultation with all stakeholders and bring it before parliament without any further delay. In this context, the committee would advise government to duly consult the Norwegian Law, which emulates this spirit to a large extent".

Can we take advantage of the beneficial aspects of recombinant DNA technology by greater investment in public good research, as for example in the breeding of crop varieties whose seeds farmers can keep and resow, rather than concentrate only on hybrids whose seeds the farmers have to buy every crop season? How can we develop institutional structures, which can help to allay the apprehensions of the public? This is the most urgent task facing the central and state governments today with reference to genetically modified crops. The sooner we address the issues raised by the parliamentary committee, the greater will be the opportunity for harnessing molecular genetics for sustainable food security.

(M S Swaminathan is an agricultural scientist who led India's green revolution)

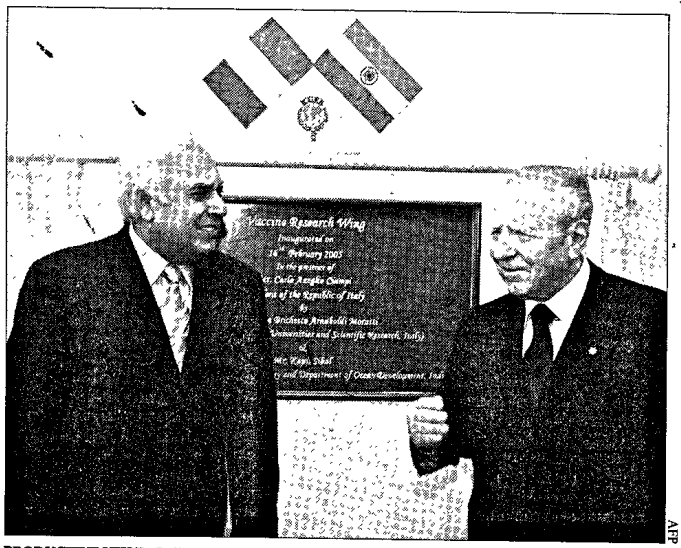

AFP

PRODUCTIVE YIELD : Italian president Carlo Azeglio Ciampi (R) talks with then science and technology minister Kapil Sibal at International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology on February 16, 2005

- Government of India is hosting International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology in New Delhi
- Genetic medicine including vaccine development and bioremediation is also making rapid progress
- Basudeb Acharia heads committee on agriculture of Indian Parliament with 31 members of parliament

Hindustan Times Lucknow 26-10-2012 P-2

FOSSIL FUEL WILL BE OVER IN 60 YRS

Strange! No leader is thinking about Plan B

BIGGER ROLE APJ Kalam asked NBRI to play a national role and set up its branch in Sundarbans and find out a bio-solution to high CO2 levels on the marshy land

HT Correspondent
lkoreportersdesk@hindustantimes.com

LUCKNOW: All fossil fuel will be exhausted in 60 years. No leader is thinking about it. Strange! There is no alternative plan, said former President APJ Abdul Kalam, addressing a question-answer session with children at the National Botanical Research Institute (NBRI) on Thursday.

He called upon the school-children to keep this in mind and find out ways and means to promote use of alternative energies including nuclear, bio, wind and solar when they have decision-making power at their disposal. Unless India addresses the problem now, it won't be able to do so when the situation really arises, he suggested implying the need for an alternative fuel plan at the earliest.

He said, "We are generating nearly 36 million tons of CO2 all over the world. We use a lot of coal. Instead we should go in for other energy resources. Energy independence is the need

Kalam was in the city for the inaugural function of NBRI's diamond jubilee celebrations.

With all praises for the expertise at NBRI, Bhartratna Kalam said, "The institute must set up its branch at the Sundarbans and nurture the rich biodiversity with their expertise. NBRI scientists should study the problems and develop a unique plant base synthesis to absorb the abundant carbon dioxide at the Sundarbans." He said satellite mapping had revealed that natural the co2 levels were very high in the area which was primarily a marshy land.

The institute should also work for the characterization of Indian cotton varieties for the larger interest of the farmers and work on some herbal plantations suitable to the cold of Jammu and Kashmir as with all beauty, not many plants survive in the intense cold weather in the area, he said and suggested that the NBRI should use its expertise for the solution of problems of bamboo clusters in the country's northeastern parts and contribute for the improvement of rubber in Kerala and help replace synthetic rubber with natural rubber.

He said the institute needed to prepare a national atlas to enable the conservation of rare species and focus on benefiting the farmers through its expertise.

Governor BL Joshi too appreciated the works of the institute and said that it was an asset for the state and country. He said, "Agriculture always needs innovations and thus the institute must focus on benefiting the sector with its technologies."

SK Brahmachari, director general CSIR said the NBRI would soon undertake the task of mapping the soil of India that would enable the government and farmers identify the land suitable for particular crop types. The mapping would facilitate the farmers to select the right crop for the right soil and maximize their profit.

NBRI director CS Nautiyal highlighted the various achievements of the NBRI and said that the institute was striving to benefit the society with its researches. Also present on the occasion was SK Sapory, chairman research council NBRI and vice chancellor JNU, New Delhi.

The guests planted some rare saplings at the NBRI lawns.

KALAM WITH SCHOOL CHILDREN

With promises for the environment by the children, Kalam interacted with the students at the NBRI. He answered their questions relating to the environment and sciences and emphasised that all children must plant trees. He said that farmers and scientists must work together.

MAKE KANPUR A CARBON-FREE CITY: KALAM

Making Kanpur a carbon neutral or carbon-free city should be every IITian's mission, said former president APJ Abdul Kalam. He was in Kanpur on Thursday to attend the golden jubilee celebrations of IIT-Kanpur's student gymkhana.

"As you study here keeping the city pollution-free is your responsibility," says the missileman. "Once Surat was as polluted as Kanpur. IITians can change the face of this city as in the case of Surat in 20 years," added Kalam.

Dr Kalam asked the students to take a pledge to do something worthwhile in their lifetime so that the world remembers them.His interaction with the students focused on the social-dharma of scientific fraternity and its role in lightening up the lives at micro-level.

"I was more content after creating a 400 gram calliper for the physically disabled than building the missiles," says Dr Kalam. He called on the students to play a proactive role in realising the vision 2020 bridging the gap between villages and cities. "Technology can end the gaping developmental and economic inequity between these two worlds," he said. About 70% of the country's population resides in the villages, which are in dire need of new technologies that help in education, healthcare, agriculture and conversation of agricultural produce."You need to play a much greater role in this direction. Only eight years are left for the goal of 2020. Time is less and the task is big," he said.

ON MISSION: 'INGNITE' THE YOUNG MINDS

- NBRI must set up its branch at the Sundarbans and nurture the rich biodiversity with their expertise. NBRI scientists should study the problems and develop a unique plant base synthesis to absorb the abundant carbon dioxide at the Sundarbans, said Kalam.
- Kalam called upon the school-children to keep in mind the limited resource and find out ways and means to promote use of alternative energies including nuclear, bio, wind and solar when they have decision-making power at their disposal.
- Unless India addresses the problem now, it won't be able to do so when the situation really arises, Kalam suggested implying the need for an alternative fuel plan.

- APJ Kalam addressing the students at Christ Church College; (above right) the former president plants a Rudraksha sapling at NBRI, and (below left) students and staff of Christ Church College surround Dr Kalam to shake hands with him. DEEPAK GUPTA/HT PHOTOS

KALAMSPEAK

Imagination leads to creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge and knowledge makes you great!

FORMER PRESIDENT APJ ABDUL KALAM AT NBRI

Hindustan ND 27/10/2012 P5

एआईसीटीई ने छात्रों को किया आगाह

60 तकनीकी शिक्षण संस्थान काली सूची में

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे 332 तकनीकी शिक्षण संस्थानों को फर्जी करार देते हुए इन्हें काली सूची में डाल दिया है। इनमें दिल्ली के 60 संस्थान शामिल हैं। छात्रों से अपील की गई है कि वे तकनीकी कालेजों में एडमिशन लेने से पूर्व एआईसीटीई की वेबसाइट पर काली सूची में दर्ज संस्थानों के बारे में जानकारी जरूर हासिल कर लें।

एआईसीटीई के चेयरमैन एस. एस. मंथा के अनुसार सबसे ज्यादा 108 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान महाराष्ट्र में हैं। जबकि दूसरे नंबर पर दिल्ली में 60 और आंध्र प्रदेश में 43 ऐसे संस्थान हैं। उन्होंने बताया कि इन संस्थानों के कोर्सों को या तो एआईसीटीई ने मंजूरी नहीं दी या कभी दी भी गई होगी तो बाद में गड़बड़ियों या खराब गुणवत्ता के चलते उसे वापस ले लिया गया। कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जिनके कुछ कोर्स तो ठीक हैं लेकिन कुछ कोर्स वे बिना मान्यता के चला रहे हैं। इसलिए छात्रों को चाहिए कि एडमिशन लेने से पूर्व अपने संस्थान के बारे में एआईसीटीई की वेबसाइट से जानकारी ले लें। वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त और अमान्य दोनों किस्मों के संस्थानों का ब्यौरा है। मंथा के अनुसार इनमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए, एमसीए और सभी किस्म के पेशेवर शिक्षण संस्थान शामिल हैं। ये छात्रों को गुमराह कर रहे हैं।

एआईसीटीई से मान्य नहीं होने के कारण उनकी डिग्री का कोई महत्व नहीं है। सरकारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी उसे नहीं माना जाएगा। न ही यह डिग्री आगे की पढ़ाई के लिए मान्य होती है। मंथा के अनुसार हर साल हम ऐसे कालेजों की जांच करते हैं और इस सूची को अद्यतन करते रहते हैं।

फर्जी संस्थान

महाराष्ट्र	108	हरियाणा	16
दिल्ली	60	उत्तर प्रदेश	16
आंध्र	43	उत्तराखंड	2
प. बंगाल	24	बिहार	2
कर्नाटक	23		

332 संस्थानों को काली सूची में डाला है एआईसीटीई ने देशभर में

October 28

Statesman Nd 28-10-2012
P-2

IIT Delhi's global footprint

statesman news service

NEW DELHI, 27 OCT: Indian Institute of Technology, Delhi, (IIT-D) is going global by collaborating with foreign universities. The institute is helping other countries start IIT-type institutes.

IIT Delhi has reached a pact with the Ethiopian University in Addis Ababa to provide video lectures to them. Both IIT Delhi and Ethiopian University have set up remote classrooms to share video lectures. Consequently, many students are being benefited. IIT Delhi is also helping Mauritius set up an institute like IIT Delhi at the behest of the ministry of human resource development.

Tribune ND 28/10/2012

P-3

IIT innovation centre to boost design projects

TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, OCTOBER 27

Ahead of the 43rd convocation ceremony of Indian Institute of Technology - New Delhi tomorrow, its director Prof R.K.Shevgaonkar has announced a new innovation centre on campus that would encourage design projects by students. The proposal in this regard has been approved by the Government of India and is likely to take shape within the next six months.

At the convocation, advisor to the Prime Minister in the National Council of Skill Development S Ramadorai will be the Chief Guest. About 1,786 pass-outs will attend the ceremony.

"This centre will encourage a more interdisciplinary approach amongst students. It will propagate three basics-first, how to generate an innovative idea; second, how to convert that innovative idea into a product; and third, to convert that product into a business. The students will always have the option of sitting for the institute's placement process. The institute has also received an initial seed capital of Rs 25 crore from the Ministry of Human Resource Development for the centre," said Shevgaonkar.

Amar Ujala ND 28/10/2012 P-6

मॉरीशस में खुलेगा आईआईटी का सेंटर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली अपने छात्रों को शिक्षित करने के साथ-साथ विदेशों में भी प्रौद्योगिकी का ज्ञान बांट रहा है। आईआईटी दिल्ली ने मॉरीशस में हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आईआईटी के प्रस्ताव को मॉरीशस सरकार ने मंजूर कर लिया है।

मॉरीशस में तैयार होने वाला यह संस्थान आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन नहीं होगा, बल्कि यह सलाहकार के रूप में मदद करेगा। इसके बाद मॉरीशस में भी आईआईटी की तरह पढ़ाई हो सकेगी। संस्थान को आईआईटी करिकुलम और मेंटरशिप देने का काम करेगा। मॉरीशस सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस योजना के लिए सहयोग देने के लिए कहा था, जिसके बाद एक टीम मॉरीशस भी गई थी।

दौरे के बाद आईआईटी ने एक प्रस्ताव तैयार कर मॉरीशस सरकार को दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। आईआईटी दिल्ली इस संस्थान के लिए मेंटरशिप का काम करेगा। इस संस्थान के लिए आईआईटी और मॉरीशस सरकार के बीच आगे की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।

बता दें कि आईआईटी दिल्ली इथोपिया के आदिस अबाबा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करा रहा है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक से आदिस अबाबा और आईआईटी में लिंक प्रोग्राम सेट अप किया गया है, जिससे वहां बैठे छात्र सवालों के जवाब प्राप्त करते हैं।

Hindustan ND 28/10/2012
P-1

जेईई एडवांस में डेढ़ लाख से अधिक को मौका

नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में दाखिले के लिए होने जा रही जेईई एडवांस्ड परीक्षा में डेढ़ लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को मौका मिल सकेगा। साथ ही जेईई (मेन) परीक्षा में परीक्षार्थी का कुल स्कोर मान्य होगा।

आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर जी.बी. रेड्डी ने बताया कि अगर जेईई (मेन) में कुछ छात्रों के अंक समान होंगे तो उन दोनों को जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा में छात्रों के कुल स्कोर को ही माना जाएगा। पहले अंक समान होने पर आईआईटी एक फॉर्मूला बनाता था जिसमें किसी विषय के अंकों के आधार पर छात्र को सीट मिलती थी। **(प्र.सं.)**

Dainik Bhaskar ND 28/10/2012
P-11

आईआईटी-जेईई केंद्रों को अलवर व बीकानेर से किया बाहर

भास्कर न्यूज. सीकर

जेईई 2013 के लिए आईआईटी ने परीक्षा केंद्रों वाले शहरों की सूची जारी कर दी हैं। इस बार अलवर व बीकानेर को परीक्षा केंद्र नहीं दिया गया है। पिछले साल ही अलवर को परीक्षा केंद्र मिला था। सीकर का परीक्षा सेंटर यथावत रखा गया है। इससे सीकर से परीक्षा में शामिल होने वाले 30 हजार अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा मिलेगा।खास बात यह है कि लंबे समय से परीक्षा सेंटर का इंतजार कर रहे कोटा को भी तगड़ा झटका लगा है। उसे इस बार भी परीक्षा केंद्र नहीं दिया गया। राजस्थान में पांच शहरों जयपुर, सीकर, अजमेर, जोधपुर व उदयपुर में परीक्षा केंद्र रहेंगे। आईआईटी की ओर से जारी सूची में दिल्ली आईआईटी जोन में सीकर व उदयपुर शहर में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए चुना गया है। पिछले साल अलवर भी शामिल था। इस बार अलवर को परीक्षा केंद्र नहीं दिया गया है। ऐसे में यहां के अभ्यर्थियों को जयपुर व सीकर में ही परीक्षा देनी पड़ेगी। बॉम्बे आईआईटी जोन में अजमेर, जयपुर व जोधपुर शहर को फिर से परीक्षा केंद्र दिया गया है।

Hindustan Times ND 28/10/2012 P-10

WINDS OF CHANGE

From schools to IITs, students play policymakers

Charu Sudan Kasturi
■ charu.kasturi@hindustantimes.com

NEW DELHI: Six months ago, Ishant Gupta was still in school, appearing for his class XII board examinations. On Friday, the commerce student sat down with academic experts as a policymaker to review the accountancy curriculum for 12,300 schools across the country and abroad that are affiliated to the Central Board of Secondary Education.

The shift may still be sinking in for the recent school graduate, who insisted that he needed to "take permission" from a senior on the CBSE expert panel before speaking to a journalist.

But, Gupta could become a mascot for a deeper shift in India's education policymaking that experts argue is long overdue and is finally taking firm roots. The CBSE decision to appoint board toppers on panels that will revise subject curricula for classes XI and XII is unprecedented among the country's school boards.

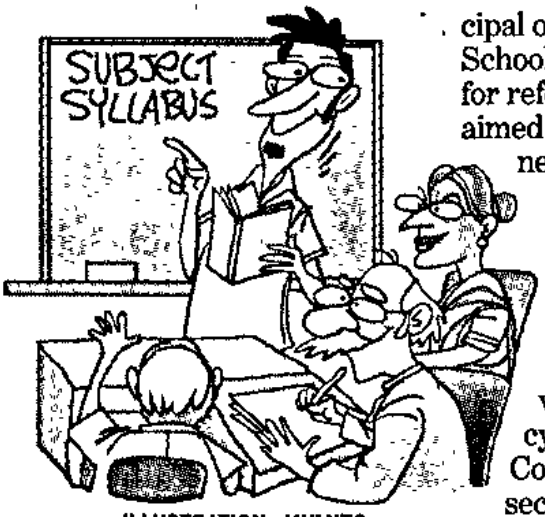

ILLUSTRATION: JAYANTO

But from individual schools to the Indian Institutes of Technology (IITs), institutions and the government are turning to students for advice in framing policies that directly affect them, after decades of policymaking that viewed students only as recipients of decisions taken by older experts.

"There's a big change in approach happening - which we needed for a while," said Avnita Bir, principal of Mumbai's RN Podar School, widely recognised for reforms and innovations aimed at better meeting needs of students. "After all, students are key stakeholders in education policies."

IIT Kanpur graduate Mukul Tuli now works with consultancy major McKinsey and Company. But science secretary T Ramasami wanted to pick his brains on reforming the IIT Joint Entrance Examination (IIT-JEE).

Appointed by HRD minister Kapil Sibal to head a panel to reform the IIT-JEE, Ramasami picked fresh IIT graduates on his team. Though the panel's recommendation to dump the IIT-JEE met with resistance, the presence of recent IIT graduates like Tuli gave its report credibility.

MORE ON THE WEB
hindustantimes.com/studentpolicy

October 29

Times Of India ND 29/10/2012
P-4

PM's adviser asks IITs to raise the bar

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Urging the IITs to reposition themselves to address the needs of the future world, Padma Bhushan Dr S Ramadorai, adviser to PM said, "We live in a dynamic work and life environment. The future will be an even more fast-changing, convergent, globalised and collaborative world. I believe that is a good place to start. Future trends in certain key sectors could provide direction to the exciting new areas where opportunities are emerging." He was delivering the 43rd convocation address of Indian Institute of Technology, Delhi on Sunday.

Citing the latest QS world university rankings, he said India is the only BRICS nation not to have a university in the top 200. China, on the other hand, has seven universities in the top 200. "This is the right time for the IITs to consider raising the bar, and look at the levers it needs to move in order to align itself better with needs of the future world," he said.

Rajesh Mehta

THREE CHEERS! IIT-D's annual convocation saw the largest number of graduates this year

Ramadorai went on to draw a blueprint as to what should IITs be doing to position themselves powerfully for the future, giving example of areas like energy, manufacturing and 3D printing technology.

The annual convocation this year saw the largest number of graduates being conferred their degrees. The numbers of PGs and PhDs have also increased. The institute conferred bachelors degrees on 586 graduates and postgraduate degree on 1,006 (up from 802 in 2011). The number of PhDs increased from last year's 173 to 199. This year, Ankur Gupta received the president's gold medal, while Shruti received the director's gold medal. Apart from them, 14 silver medalists were also honoured during the convocation.

IIT-D introduced a distinguished alumni awards category this year and the awardees for 2012 were professor Trilochan Sastry of IIM, Bangalore; professor R C Budhani, director, National Physical Laboratory, New Delhi; Punita Kumar Sinha, founder and managing partner, Pacific Paradigm Advisors; and professor Pawan Sinha, Massachusetts Institute of Technology, USA. The institute also honoured 19 faculty members with the teaching excellence award this year.

Financial Chronicle ND 29/10/2012

P-10

PM adviser for more foreign students in IITs

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi

OBSERVING that IITs need to develop a more 'outward looking' profile to achieve higher global rankings, adviser to PM on skills development, S Ramadorai, favoured having significant number of foreign students in these institutes.

"Clearly the IITs cannot be among the top global institutions without a significant proportion of foreign students," Ramadorai said. He also suggested student participation in innovation and well funded collaborative projects while studying BTech which could lead to increased numbers going for PhD programme.

"In the days to come could we also see the IITs being consulted by the government on say technology policy. Even if it is a slow start, the learning curve in such consultations would be invaluable to both IITs and the country in the long run," he said.

As India is largely a technology importer, Ramadorai said the trend needs to be reversed with the close interaction IITs and Indian industry. "Industry in turn need to be ready to partner and fund medium to long term R&D research at the IITs".

Leveraging on the brand name of the IITs, he said these institutes can position themselves more powerfully, by tapping on the opportunities available in different sectors in keeping with the future tends and requirements in mind.

Business Line ND
29/10/2012 P-13

'IITs need to take more foreign students'

Press Trust of India
New Delhi, Oct 28

Observing that the Indian Institutes of Technology (IITs) need to develop a more "outward-looking" profile to achieve higher global rankings, advisor to Prime Minister on skills development S. Ramadorai said on Sunday that he favoured having a significant number of foreign students in these institutes.

"Clearly the IITs cannot be among the top global institutions without a significant proportion of foreign students," Ramadorai said delivering the 43rd convocation address of IIT Delhi here.

He also suggested student participation in innovation and well-funded collaborative projects while studying B.Tech which could lead to increased numbers going for Ph.D programme.

"In the days to come could we also see the IITs being consulted by the government on say technology policy Even if it is a slow start, the learning curve in such consultations would be invaluable to both IITs and the country in the long run," he said.

As India is largely a technology importer, Ramadorai said the trend needs to be reversed with the close interaction IITs and Indian industry. "Industry in turn needs to be ready to partner and fund medium to long term R&D research at the IITs."

Leveraging on the brand name of the IITs, he said these institutes can position themselves more powerfully by tapping on the opportunities available in different sectors in keeping with the future tends and requirements in mind.

Rashtriya Sahara ND
29/10/2012 P-7

आईआईटी में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या बढ़े : रामादुरई

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रधानमंत्री के सलाहकार एम रामादुरई ने कहा कि आईआईटी को वर्ल्ड क्लास संस्थान बनाने के लिए इसमें विदेशी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है तभी आईआईटी विश्व के शीर्ष संस्थानों की रैंकिंग में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता की जरूरत होती है, लेकिन विदेशी विद्यार्थियों के लिए ऐसी सहायता का प्रावधान नहीं है। उद्योग जगत इसके लिए सहायता करें। हालिया मैकिंसी रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन डॉलर की होगी और जनसंख्या 1.5 बिलियन। 2030 के भारत का अभी 80 फीसद निर्माण, और होना है। रामादुरई रविवार को आईआईटी दिल्ली के 43वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर आईआईटी दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन डॉ. विजय पी. भटकर व निदेशक प्रो. आरके शिवगांवकर मौजूद थे।

▶ आईआईटी दीक्षांत समारोह में वितरित हुईं 1786 उपाधियां

आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. आरके शिवगांवकर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सोनीपत में आईआईटी दिल्ली के एक्सटेंशन सेंटर खोले जाने को लेकर 50 एकड़ जमीन प्रदान की है। जमीन के ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी है। आईआईटी दिल्ली ने दोबारा से हरियाणा सरकार से झज्जर जिले के भदसा गांव में 125 एकड़ जमीन की मांग की है। हरियाणा सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद है कि यहां भी आईआईटी को जमीन मिल जाएगी। यहां भी एक्सटेंशन सेटर खोला जाएगा जिसमें शैक्षणिक व शोध से जुड़े कार्य होंगे।

उन्होंने कहा कि आईआईटी का प्रयास है कि किसी भी आर्थिक रूप से गरीब विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित न किया जाए। इसके लिए व्यक्तिगत, ट्रस्ट व विभिन्न संगठनों की सहायता से स्कॉलरशिप के माध्यम से गरीब विद्यार्थियों की सहायता की जाती है। वर्तमान में 168 विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर अवार्ड, स्कॉलरशिप के माध्यम से यह सहायता दी जा रही है। विद्यार्थियों की मदद के लिए लोन स्कॉलरशिप योजना भी चलाई जाती है जिसमें उन्हें बैंकों से लोन दिया जाता है। प्रो. शिवगांवकर ने कहा कि बीते कुछ सालों से आईआईटी दिल्ली में दाखिला लेने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है।

सेशन 2011-12 में करीब 3258 स्नातक और 4212 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का दाखिला हुआ है। इनमें छात्राओं की संख्या 1316 है। इसके अलावा पांच देशों के 17 विद्यार्थियों ने भी सेशन 2011-12 में दाखिला लिया था। समारोह में अंकुर गुप्ता को प्रेजिडेंट गोल्ड मेडल व श्रुति को डायरेक्टर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। सेशन 2011-12 के लिए 1786 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए जिनमें से 199 ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके अलावा 100 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल, पुरस्कार व अवार्ड से नवाजा गया।

Virat Vaibhav ND
29/10/2012 P-15

आईआईटी में विदेश विद्यार्थियों की संख्या बढ़े : रामादुरई

नई दिल्ली। कौशल विकास पर प्रधानमंत्री के सलाहकार एस रामादुरई ने औद्योगिक संस्थानों (आईआईटी) में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का आज समर्थन किया। उनका मानना है कि इन संस्थानों को वैश्विक स्तर पर ऊंची रैंकिंग के लिए अपने यहां विदेशी विद्यार्थियों की संख्या बढानी होगी। वे यहां आईआईटी दिल्ली के 43वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से विदेशी विद्यार्थियों की अच्छी खासी संख्या के बिना ए संस्थान(आईआईटी) शीर्ष वैश्विक संस्थानों में नहीं आ सकते। उन्होंने नवोन्मेष गतिविधियों में विद्यार्थियों की अधिक भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत मुख्य रूप से प्रौद्योगिक का आयात है और इस रूख को पलटे जाने की जरूरत है। इस बारे में भारतीय उद्योग जगत तथा आईआईटी में करीबी संबंधों पर जोर उन्होंने दिया। इस अवसर पर 1,786 उत्तीर्ण विद्यार्थी उपस्थित थे जिनमें से 199 पीएचडी धारक हैं। ■

Dainik Bhaskar, ND 29/10/2012 p-2

आईआईटी में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए : रामादुरई

नई दिल्ली. आईआईटी दिल्ली के 43वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मौजूद प्रधानमंत्री के सलाहकार एस. रामादुरई ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारतीय औद्योगिक संस्थान को ऊंची रैंकिंग हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि यहां विदेशी छात्रों की तादाद बढ़ाई जाए। रविवार को आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने नवोन्मेष गतिविधियों में बीटेक के छात्र-छात्राओं की अधिक से अधिक भागीदारी पर भी जोर दिया, जिससे पीएचडी प्रोग्राम में लोगों की संख्या में इजाफा हो सकेगा। इस दीक्षांत समारोह में इस साल उत्तीर्ण 1,786 छात्र उपस्थित थे जिनमें 199 पीएचडी धारक थे। इस मौके पर इन्हें डिग्रियां भी बांटी गईं।

Hari Bhumi ND 29/10/2012

p-2

आईआईटी का दीक्षांत समारोह संपन्न

नई दिल्ली। कौशल विकास पर प्रधानमंत्री के सलाहकार एस. रामादुरई ने भारतीय औद्योगिक संस्थानों (आईआईटी) में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने का समर्थन किया। उनका मानना है कि इन संस्थानों को वैश्विक स्तर पर ऊंची रैंकिंग के लिए अपने यहां विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उन्होंने ये बातें आईआईटी दिल्ली के 43वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से विदेशी छात्रों की अच्छी खासी संख्या के बिना ये संस्थान आईआईटी शीर्ष वैश्विक संस्थानों में नहीं आ सकते। उन्होंने नवोन्मेश गतिविधियों में छात्रों की अधिक भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि भारत मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी का आयात करता है और इस रुख को पलटे जाने की जरूरत है। इस बारे में भारतीय उद्योग जगत तथा आईआईटी में करीबी संबंधों पर जोर उन्होंने दिया। इस अवसर पर 1,786 उत्तीर्ण विद्यार्थी उपस्थित थे जिनमें से 199 पीएचडी धारक हैं।

Virat Vaibhav ND
29/10/2012 P-3

आईआईटी का 43वां दीक्षांत समारोह

नई दिल्ली। भारतीय औद्योगिक संस्थान (आईआईटी) दिल्ली ने अपना 43वां दीक्षांत समारोह मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के सलाहकार एस रामादुरई ने भारतीय औद्योगिक संस्थानों में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने का समर्थन किया। उनका मानना है कि इन संस्थानों को वैश्विक स्तर पर ऊंची रैंकिंग के लिए अपने यहां विदेशी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ानी होगी। बिना विदेशी विद्यार्थियों की अच्छी संख्या के इन संस्थानों की गिनती शीर्ष वैश्विक संस्थानों में नहीं हो सकती। उन्होंने नवोन्मेश गतिविधियों में विद्यार्थियों की अधिक भागीदारी पर जोर दिया। भारत मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी का आयात करता है और इस रुख को पलटे जाने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में 1,786 उत्तीर्ण विद्यार्थी उपस्थित थे जिनमें से 199 पीएचडी धारक हैं। ■

Rashtriya Sahara ND
29/10/2012 P-7

आईआईटी : टफ एंट्रेंस तो पास कर गए, बाद में पढ़ाई लगी मुश्किल

राकेश नाथ/एसएनबी

नई दिल्ली। आईआईटी में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी कठिन एंट्रेंस टेस्ट तो पास कर जाते हैं लेकिन दाखिला लेने के बाद वे यहां की कठिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आईआईटी दिल्ली में भी ऐसे विद्यार्थी नजर आए जो पढ़ाई में कमजोर निकले। आईआईटी दिल्ली ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए अपने नए शैक्षणिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित करने को स्पेशल स्टूडेंट एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं जो ऐसे विद्यार्थियों के बारे में पता करते हैं। इस जानकारी के बाद आईआईटी दिल्ली द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष अतिरिक्त क्लासेज आयोजित की जाने लगी हैं।

आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. आरके शिवगांवकर के अनुसार संस्थान के सभी विभागों में ऐसे स्पेशल स्टूडेंट एडवाइजर की नियुक्ति की गई है जो ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाते हैं जो पढ़ाई में कमजोर हैं। ऐसे विद्यार्थियों का पता पहला सेमेस्टर शुरू होने के शुरुआती दिनों में लगा लिया जाता है। जिससे शुरुआती स्तर पर पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों को सशक्त बनाया जा सके। स्टूडेंट एडवाइजर द्वारा ऐसे विद्यार्थियों की उपस्थिति और उनके प्रदर्शन पर पूरी नजर रखते हैं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के हिसाब से उनमें सुधार करने के लिए एडवाइजर मदद करते हैं। प्रो. शिवगांवकर के अनुसार एंट्री लेबल पर लर्निंग स्लिक को बढ़ावा देने को स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है। विद्यार्थियों की अंग्रेजी भाषा, कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप को मजबूत किया जाता है। यह प्रोग्राम केरल के सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से कराया गया है। उन्होंने बताया कि 2013 में आईआईटी व आईएसएम में दाखिले के दो स्तर की परीक्षाएं जेईई मेन व एडवांस के जरिए होंगे।

▶ **आईआईटी दिल्ली ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए की विशेष व्यवस्था**

HT Mumbai

IIT-JEE NEW EXAM FORMAT

49.5% reserved category candidates in JEE (adv)

Bhavya Dore
bhavya.dore@hindustantimes.com

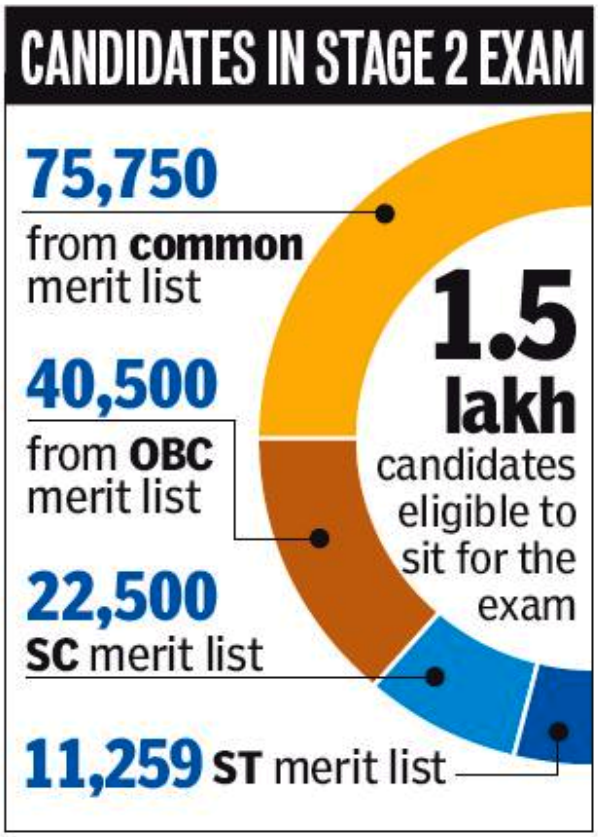

MUMBAI: General candidates will have to be in the top 75,750 candidates in the Joint Entrance Exam-Main (JEE-Main) overall merit list to make it for the second-stage exam for entry to the Indian Institutes of Technology (IITs) next year. The remaining candidates will be drawn from reserved category merit lists. A new notification has been issued by the IITs.

Totally, 1.5 lakh candidates who crack the JEE-Main will be able to sit for the JEE-Advanced; the two-step format introduced from 2013. The top 75,750 (which may include reserved candidates) will be eligible for the next exam. Of the rest, 40,500 will be the top OBC (Non Creamy layer) candidates, 22,500 Scheduled Caste and 11,250 Scheduled Tribe candidates. "The logical thing to do was to shortlist candidates in proportion to seats allotted at the IITs."

Business Standard ND 29/10/2012
P-7

कैट को अंतरराष्ट्रीय टैग

आईआईएम में दाखिले की परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे विदेशी छात्र

कल्पना पाठक

प्रवासी भारतीय (एनआरआई) और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अगले साल से कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) में हिस्सा ले सकेंगे। इस जांच परीक्षा का संचालन भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) करते हैं, जिसे वर्ष 2013 से अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने वाली है।

मौजूदा व्यवस्था के तहत आईआईएम में दाखिला लेने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ग्रैजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूट टेस्ट (जीमैट) देना पड़ता है।

आईआईएम में दाखिले के लिए होने वाली जांच परीक्षा के संचालन में साझेदार प्रोमेट्रिक आईआईएम और कैट परीक्षा को अंतरराष्ट्रीय फलक पर पहुंचाएगी। भारत में कंप्यूटर आधारित कैट परीक्षा के संचालन के लिए प्रोमेट्रिक ने आईआईएम के साथ पांच वर्षों का अनुबंध किया है। इस कंपनी ने पहले बिजनेस स्टैंडर्ड से इस बात की पुष्टि की थी कि वह कैट का आयोजन विदेशी बिजनेस स्कूलों में करने में आईआईएम के साथ साझेदारी करेगी।

एक आईआईएम के निदेशक ने कहा, 'हम इस साल अक्टूबर में कैट को वैश्विक बनाने की योजना बना रहे थे। लेकिन लागत संबंधी कुछ समस्याओं की वजह से अब यह काम अगले साल ही किया जा सकेगा। यदि कैट वैश्विक फलक पर पहुंचती है, तो रणनीतिक रूप से इसका तगड़ा महत्त्व होगा।'

आईआईएम के निदेशक ने बताया कि आईआईएम ने एक नया करार किया है, जिसकी बदौलत उन्हें स्वतंत्र तरीके से परिचालन की आजादी मिली है और वे इस करार पर अमल का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद ही कैट को अंतरराष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने की योजना कामयाब हो पाएगी।

एक अन्य आईआईएम के निदेशक ने कहा, 'ऐसे कई देश हैं, जहां उसी तरह के छात्र हैं जैसे भारतीय होते हैं। कई एशियाई देशों ने पहले से ही गुजारिश कर रखी है कि कैट का आयोजन उनके यहां भी किया जाए। मैं समझता हूं कि यह बड़ा कदम है।'

Economic Times ND 29/10/2012 P-8

सरकारी ऑर्डर से गुलजार होगा टैबलेट का बाजार

MIT के मुताबिक सरकार के प्लान को देखते हुए एक करोड़ टैबलेट की रिक्वायरमेंट

[शैली सिंह *नई दिल्ली*]

सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो सोचा है, अगर उस पर अमल होता है तो टैबलेट बाजार में गरमाहट बढ़ सकती है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टाफ की कंप्यूटिंग की जरूरत पूरी करने या राजनीति चमकाने के लिए आम लोगों, खासतौर पर बच्चों को सस्ते टैबलेट बांटने का प्लान बनाया है।

हार्डवेयर बॉडी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एमएआईटी) के मुताबिक, सरकारों के प्लान को देखते हुए एक करोड़ टैबलेट की जरूरत पड़ेगी। रिसर्च फर्म आईडीसी के मुताबिक, यह इस साल की अनुमानित सेल्स के पांच गुना के बराबर होगा। गार्टनर इंडिया के प्रिंसिपल रिसर्च एनालिस्ट के मुताबिक, 'सरकार टैबलेट की डिमांड बढ़ा रही है।' इस साल जनवरी में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सामाजिक, आर्थिक और जाति के आधार जनगणना करने को अपने स्टाफ के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से 72 डॉलर (3,600 रुपए) के रेट पर सोलर पावर से चलते 6 लाख टैब्लेट खरीदे थे। एचआरडी मिनिस्ट्री का 58.60 लाख टैबलेट का ऑर्डर पाइपलाइन में है। मिनिस्ट्री का 35 डॉलर (1,750 रुपए) के सब्सिडाइज्ड रेट पर टैबलेट बांटने का प्लान है। प्लान के पहले फेज में एक लाख आकाश टैबलेट बंटने हैं। आकाश के दूसरे वर्जन को कनाडा की कंपनी डाटाविंड अगले महीने रिलीज करेगी। कम से कम चार राज्यों- गोवा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से बड़े ऑर्डर आने हैं। इनमें पिछले दो साल में हुए चुनाव में (अभी के) सत्ताधारी पार्टी ने टैबलेट्स का वादा किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं की परीक्षा पास करने वाले हरेक स्टूडेंट को एक फ्री टैबलेट देने का वादा किया है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को टैबलेट देने का वादा किया है। पेपर की खपत घटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के लिए 795 टैबलेट खरीदे जाने का प्लान है। एसचसीएल इंफो के मोबिलिटी हेड गौतम आडवाणी कहते हैं, 'यह ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी जैसी है। (इसमें कंपनियां मौजूदा कस्टमर के लिए आपस में कॉम्पिटिशन करने के बजाय नए कस्टमर ढूंढती हैं। प्लान पर अमल होना बाकी है। ऐसा हुआ तो ग्रोथ बढ़ेगी।'

बढ़ेगी डिमांड

कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने आम लोगों, खासतौर पर बच्चों को सस्ते टैबलेट बांटने का प्लान बनाया है

आईडीसी के मुताबिक, 2011 में ढाई लाख टैबलेट बिके थे। 2012 में सेल्स 17.4 लाख तक पहुंच सकती है। गार्टनर के त्रिपाठी कहते हैं, 'पीसी मार्केट को सरकार से बढ़ावा मिल रहा है। डिमांड पूरी करने के लिए मार्केट में लगभग 70 टैबलेट मेकर्स हैं। टैबलेट की पहुंच आम लोगों तक बनाने के लिए एक लेवल तक कीमत में कमी और इंटरनेट की उपलब्धता में बढ़ोतरी जरूरी है।' एमएआईटी के प्रेसिडेंट आलोक भारद्वाज के मुताबिक, सरकारी ऑर्डर लो कॉस्ट टैबलेट के होंगे। टैबलेट मेकर विशटेल के एमडी मिलिंद शाह कहते हैं, 'सरकार लंबे समय से किफायती कंप्यूटिंग सिस्टम हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस डिमांड को टैबलेट पूरा करेंगे।'